

12.57 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Distribution of Surplus Land to the poor for effective implementation of the 20 Point Programme

श्रीमती ऊषा वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर तथा ग्रामीणों में जो भी छोटी बड़ी योजनायें लागू की गई हैं, चाहे वह बैंक के द्वारा हो या ब्लाक के द्वारा, उनसे जो लाभ गरीबों को मिलना चाहिए वह उनको नहीं मिल रहा है। जैसे डी०आर०आई० को लीजिए। इसको लेने के लिए जो व्यक्ति जाता है उसको एक-एक वर्ष तक दौड़ाते रहते हैं जिससे गरीब व्यक्तियों को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है।

यही नहीं जिन गरीब लोगों को भूमि आवंटित की गई है उनको भी विशेष परेशानी उठानी पड़ती है। मेरे प्रान्त में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन लोगों को पट्टे मिले हैं उनको अभी तक यह भी पता नहीं है कि हमारी ज़मीन कहां पर है। वे अपने गांवों से डिस्ट्रिक्ट तक हजारों बार चक्कर लगा चुके हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मजदूर व्यक्ति अपने बच्चों का पालन-पोषण करने में भी असमर्थ हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो भी ज़मीनें सीलिंग की ग्राम समाज की हैं उनको वह अपने कब्जे में लेकर उन गरीबों को बांटें जिससे वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें।

गरीब कृषक को ज़मीन का समुचित उपयोग करने हेतु बीज, खाद एवं अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए सरकार पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करें, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाए ताकि वे लोग सुख शांति की जिन्दगी जी सकें और उनके बच्चों का जीवन सुखमय हो सके।

मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि वह इस ओर विशेष ध्यान देकर तत्काल इस कार्य को क्रियान्वित करे ताकि बीस सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

13 hrs.

(ii) Measures for stopping felling of green trees in Purnea and other parts of Bihar

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में पर्यावरण में सुधार करने के लिए सारे विश्व में ध्यान दिया जा रहा है। आज हम भली प्रकार जानते हैं कि प्रकृति और राष्ट्रीय समृद्धि में परस्पर गहरा संबंध है। पेड़-पौधों का व्यक्ति के स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति और वातावरण से आज संबंध निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है। लेकिन यह खेद का विषय है कि बिहार के पूर्णिया ज़िले में हरे-पेड़ों की विवेकहीन ढंग से कटाई हो रही है। इससे सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित है। भविष्य में यह क्षेत्र रेगिस्तान में बदल कर सूखे की आशंका से घिर जाएगा और स्थानीय आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी काफी कठिनाइयां पैदा कर देगा। जो लोग अधिकांश वन-सम्पदा पर निर्भर रहते हैं, आज पेड़ों की अवैध कटाई से इन निर्धन लोगों का शोषण हो रहा है। पूर्णिया किसी समय पूर्णिया आम की अच्छी किस्म के लिए विख्यात था, लेकिन उनके लिए वरदान स्वरूप आम के पेड़ धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। इन पेड़ों की अवैध कटाई में स्थानीय असामाजिक तत्वों का हाथ है और वे लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं। पूर्णिया ज़िले में आम के पेड़ों की एक तिहाई संख्या अवैध कटाई का शिकार बन चुकी है और वनों की कटाई अब भी निरन्तर जारी है। असली अपराधियों को आज तक नहीं पकड़ा गया है, जबकि बिना सोचे समझे यह आरोप आदिवासियों पर थोप दिया जाता है। पेड़ों को काटने से गरीब वर्ग के लोगों का जीवन-निर्वाह होता था, अब उन्हें पकड़कर पुलिस ले जाती है और यह लकड़िया ठेकेदारों द्वारा चार गुना कीमत में बिकती हैं।

मेरा निवेदन है कि पेड़ों की अवैध कटाई